इलाहाबाद जिला कंपनी.परिचालन

बैंक लिमिटेड., इलाहाबाद

बनाम

विध्या वारिध मिश्रा

11 अगस्त, 2004

(एस. एन. वरियावा और ए. के. माथुर, जे. जे.,)

सेवा कानूनः

सेवा समाप्ति-कर्मचारी के खिलाफ आरोप-अनुशासनात्मक कार्यवाही और आपराधिक मुकदमा-अनुशासनात्मक कार्यवाही में प्राधिकरण द्वारा दी गई मामूली सजा-मामूली सजा को मंजूरी नहीं दी गई और बाद में सेवाओं को समाप्त कर दिया गया-आपराधिक न्यायालय द्वारा बरी किया गया प्राधिकरण द्वारा खारिज की गई समाप्ति पर फिर से विचार करने के लिए आवेदन-लिखित याचिका-अवधि आदेश को चुनौती नहीं दी गई- नीचे दिए गए न्यायालयों ने इस आधार पर बहाली का निर्देश दिया कि दोहरी सजा दी गई-अपील पर यह कहा गया बहाली सही नहीं थी क्योंकि कोई दोहरी सजा नहीं दी गई थी क्योंकि मामूली सजा नहीं दी गई थी-इसके अलावा क्योंकि समाप्ति आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी-अनुशासन प्राधिकरण आपराधिक से अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकता है।

अदालत कार्यकारी समिति ने दो वार्षिक वेतनवृद्धि को रोकने और चरित्र सूची में प्रतिकूल प्रविष्टियों को दर्ज करने के लिए दंड का प्रस्ताव रखा। हालांकि, सहकारी समितियों के पंजीयक ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उनकी सेवाओं को समाप्त करने की राय दी। अतः उनकी सेवाएँ थीं, समाप्त कर दी। अपराध के लिए आपराधिक मुकदमे में प्रतिवादी को दोषी ठहराया गया था।

निचली अदालत द्वारा लेकिन अपीलीय अदालत द्वारा आरोपों से बरी कर दिया गया था। बरी होने के बाद उन्होंने बर्खास्तगी के आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए बैंक में आवेदन दायर किया, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की लेकिन उसमें बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती नहीं दी। उच्च न्यायालय ने याचिका को यह मानते हुए स्वीकार कर लिया कि उन्हें एक ही अपराध के लिए दोहरी सजा दी गई थी, यानी दो रद्द वेतन वृद्धि को रोकना और चरित्र सूची में प्रतिकूल प्रविष्टि और सेवाओं की समाप्ति भी। इस आदेश को उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गयी।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि समाप्ति दंडादेश के आधार पर की गई थी। प्रत्यर्थी को रिट याचिका में संशोधन करने के लिए यह दिखाने के लिए कि समाप्ति आपराधिक मुकदमे में दोषसिद्धि के आधार पर थी।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया कि-

1. कोई दोहरी सजा नहीं थी। पहले का प्रस्ताव पंजीयक द्वारा मामूली सजा देने की मंजूरी नहीं दी गई थी। इसलिए मामूली सजा नहीं दी गई थी या नहीं दी गई थी। गबन में प्रत्यर्थी की भागीदारी साबित हो गई है, एक अनुशासनात्मक जांच में उचित सजा सेवाओं को समाप्त करना था। इसके अलावा रिट याचिका में समाप्ति के आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी। इसके लिए कोई चुनौती नहीं है, आदेश बहाली का निर्देश नहीं दिया जा सकता था। (482.ई.एफ.)

2.1. बर्खास्तगी एक अनुशासनात्मक जांच के अनुसार थी। एक अनुशासनात्मक जांच में एक से अलग निष्कर्ष पर पहुंचा आपराधिक अदालत में पहुँचा जा सकता है। आपराधिक अदालत में दोषी साबित करने के लिए आवश्यक सबूत का सख्त बोझ, अनुशासन में आवश्यक नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिवादी ने यह दावा नहीं किया था कि अनुशासनात्मक प्रत्यर्थी को दोषमुक्त कर दिया गया, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। (482-एच; 483-ए-बी)

2.2. यह स्पष्ट है कि बर्खास्तगी का आदेश अनुशासनात्मक कार्यवाही में दिए गए निष्कर्षों पर आधारित था। इन निष्कर्षों पर यह नहीं कहा जा सकता है कि समाप्ति का आदेश सही नहीं था और इसलिए मामले को

उच्च न्यायालय में वापस नहीं भेजा जा सकता है।(483-सी; 483-बी,)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 5179/2004

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एस.ए. सं. 214/1998 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

अमरेंद्र शरण, डी. के. गोस्वामी और मुकेश के. गिरि अपीलार्थी।

एम. एन. राव, सत्य मित्र गर्ग और श्रीमती मंजू अग्रवाल उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था-

एस. एन. वरियावा, जे,:

अनुमति दी गई।

पार्टियों के बारे में सुना।

यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 20 जुलाई, 2001 के दिनांकित फैसले के खिलाफ है।

संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं-

प्रत्यर्थी अपीलार्थी बैंक क्लर्क -सह-कैशियर के रूप में काम कर रहा था अक्टूबर 1978 में उन्हें 15,000 रुपये के गबन के मामले में निलंबित कर दिया गया था। उत्तरदाता के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच की गई अनुशासनात्मक जाँच में गबन में प्रतिवादी का हाथ पाया गया। जाँच अधिकारी ने सेवाओं की समाप्ति और धन की वसूली के लिए दंड का

प्रस्ताव रखा।

ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक की प्रशासनिक समिति ने निर्णय लिया है कि दो वार्षिक वृद्धि और चरित्र सूची में प्रतिकूल प्रविष्टियाँ दर्ज करना । जब यह प्रस्ताव सहकारी समितियों के पंजीयक को भेजा गया तो पंजीयक ने कहा कि आरोप गंभीर थे और उन्हें अनुशासनात्मक जांच में साबित माना गया था। यह राय दी गई थी कि इन आरोपों पर समाप्ति होनी चाहिए। इसलिए पंजीयक ने मंजूरी नहीं दी। प्रत्यर्थी पर लघु दंड अधिरोपित करने का प्रस्ताव।

इस प्रकार बैंक ने प्रत्यर्थी को बर्खास्त करने का निर्णय लिया। 6 अप्रैल 1989 के एक पत्र द्वारा प्रतिवादी की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था।

यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी पर भी आरोप पत्र लगाया गया था और आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ा। निचली अदालत ने प्रतिवादी को दोषी पाया था और उसे दोषी ठहराया। हालांकि 6 अप्रैल,1989 के बाद अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि वह केवल अपने कर्तव्यों में लापरवाही कर रहा था और कोई आपराधिक अपराध नहीं किया गया था।

अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को दोषमुक्त किए जाने के बाद उन्होंने अपीलार्थी बैंक को आवेदन.समाप्ति के आदेश पर पुनर्विचार करने के

लिए एक आवेदन पेश किया। यह आवेदन 20 दिसंबर ए 1991 को खारिज कर दिया गया था।

प्रतिवादी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। 20 दिसंबर, 1991 के आदेश को चुनौती देना। इस रिट याचिका में 6 अप्रैल, 1989 के समाप्ति आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई थी।इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और बहाली का निर्देश दिया।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि:-

इसी अधिनियम के लिए प्रत्यर्थी दो वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने की सजा पहले ही दी जा चुकी थी। पीठ ने कहा कि कोई दोहरी सजा नहीं थी क्योंकि पहले के प्रस्ताव को पंजीयक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। डिवीजन बेंच का मानना है कि बैंक यदि उन्होंने स्वयं सोचा था कि केवल एक मामूली सजा देना उचित है तो वे अब प्रतिवादी की सेवाओं को समाप्त नहीं कर सकते थे।

पंजीयक द्वारा मामूली सजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई थी। इसलिए मामूली सजा नहीं दी गई थी या थोपा गया। हमारे विचार में खंड पीठ ने स्पष्ट रूप से गलती की है। गबन में प्रत्यर्थी की भागीदारी साबित होने के बाद एक अनुशासनात्मक जांच में उचित सजा सेवाओं की समाप्ति थी। अधिक महत्वपूर्ण विशेष रूप से, विद्वान एकल न्यायाधीश के

साथ-साथ खंड पीठ दोनों ने इस तथ्य की पूरी तरह से अनदेखी की कि समाप्ति दिनांकित आदेश द्वारा की गई थी।

उसका विश्वास उन्होंने प्रस्तुत किया कि जैसा कि उनकी दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया गया है नीचे दिए गए न्यायालय प्रत्यर्थी को बहालकरने में सही थे। हम इस निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

बर्खास्तगी एक अनुशासन के अनुसार थी पूछताछ की। यह तय किया गया कानून है कि एक अनुशासनात्मक जांच में एक निष्कर्ष अलग है जिस पर आपराधिक न्यायालय द्वारा पहुँचा गया है या उस पर पहुँचा जा सकता है।

अनुशासनात्मक कार्यवाही में आपराधिक न्यायालय में अपराध स्थापित करने के लिए आवश्यक सबूत का सख्त बोझ आवश्यक नहीं है। प्रत्यर्थी ने दावा नहीं किया था कि अनुशासनात्मक कार्यवाही निष्पक्ष रूप से नहीं की गई। चूँकि समाप्ति अनुशासनात्मक समिति के निष्कर्षों पर आधारित थी, इस तथ्य का कि अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी को दोषमुक्त कर दिया, कोई परिणाम नहीं था।

श्री राव ने इसके बाद कहा कि मामले को वापस भेज दिया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी को अपनी रिट याचिका में संशोधन करने और न्यायालय को यह दिखाने का अवसर दिया कि समाप्ति का आदेश

आधारित था।

प्रतिवादी के आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने पर। हम असमर्थ हैं। इस अनुरोध को भी स्वीकार करना। हम सभी दस्तावेजों को देख चुके हैं। यह स्पष्ट है कि समाप्ति का आदेश दिए गए निष्कर्षों पर आधारित था। अनुशासनात्मक कार्यवाही में। इन निष्कर्षों पर यह नहीं कहा जा सकता है कि समाप्ति का आदेश सही नहीं था।

इन परिस्थितियों में अपील की अनुमति दी जाती है।

रद्द आदेश के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

के.के. टी. अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राम कन्या सोनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।